दिनांक 02.08.2017 को 3.30 बजे अपराह्न में कृषि विभाग विकास भवन, पटना के सभा कक्ष में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की कृषि की उपसमिति की बैठक की कार्यवाही।

1. उपस्थिति : पंजी में संधारित।
2. प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य सरकार द्वारा कृषि ऋण पर 1% ब्याज अनुदान मद में नवार्ड को उपलब्ध कराई गई 10 करोड़ रूपये का बैंकवार व्यय की समीक्षा की गई। सहायक महाप्रबंधक, नबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय पटना द्वारा बतलाया गया कि ग्रामीण बैंकों से कुल 1 करोड़ 46 लाख 16 हजार का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, अन्य बैंकों से अप्राप्त है। प्रधान सचिव, कृषि विभाग द्वारा इस योजना अन्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र बैंकों से शीघ्र प्राप्त कर व्यय की गई राशि की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने का निदेश दिया गया।

   (कार्रवाई–सहायक महाप्रबंधक, नवार्ड, पटना)
3. सहायक महाप्रबंधक, नवार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना द्वारा उपस्थित बैंक अधिकारियों से वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य सरकार द्वारा नवार्ड को कृषि ऋण पर 1% ब्याज अनुदान योजना अन्तर्गत उपलब्ध करायी गई राशि एवं नवार्ड द्वारा बैंकों को विमुक्त की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। उन्होंने सामान्य वर्ग के कृषक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कृषक मद में कर्णांकित राशि के अनुसार व्यय प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु बैंक अधिकारियों से अनुरोध किया।

   (कार्रवाई–सहायक महाप्रबंधक, एस०एल०बी०सी०, पटना)
4. प्रधान सचिव, कृषि विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में कृषि ऋण पर 1% ब्याज अनुदान योजना की स्वीकृति हेतु राशि की आवश्यकता के सम्बन्ध में बैंक अधिकारियों/नवार्ड के पदाधिकारियों से जानकारी ली गई। सहायक महाप्रबंधक, नवार्ड द्वारा बतलाया गया कि बैंकों से गत वित्तीय वर्ष का 50% उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद राशि की आवश्यकता का आकलन किया जा सकता है। प्रधान सचिव, कृषि विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए इस योजना अन्तर्गत राशि की आवश्यकता सम्बन्धी प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया ताकि योजना की स्वीकृति शीघ्र की जा सके।

   (कार्रवाई–सहायक महाप्रबंधक, नवार्ड, पटना)
5. पंजाब नेशनल बैंक के प्रतिनिधि द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 में समय पर ऋण की अदायगी करने वाले के० सी० सी० खाताधारक कृषकों को अल्पावधि फसल ऋण पर 1% ब्याज अनुदान मद में 20,80,865(बीस लाख अस्सी हजार आठ सौ पैंसठ) रूपये का समायोजन समय पर नवार्ड को दावे प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण नहीं होने तथा राशि के भुगतान के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई की जानकारी ली गई। सहायक कृषि निदेशक(सांख्यिकी) द्वारा बतलाया गया कि वित्त विभाग, बिहार, पटना की पृच्छा के क्रम में मुख्य महाप्रबंधक, नवार्ड, पटना से वर्ष 2012–13 में MOU का प्रावधान तथा पंजाब नेशनल बैंक द्वारा नवार्ड को दावे प्रस्तुत करने की तिथि की जानकारी हेतु पत्र लिखा गया है। सूचना अप्राप्त है।

   (कार्रवाई–मुख्य महाप्रबंधक, नवार्ड, पटना)
6. नवार्ड के प्रतिनिधि द्वारा बतलाया गया कि कृषि रोड मैप में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए Credit Component दिया गया है। सम्बन्धित Component में बैंक Finance की आवश्यकता को उस Sector के Expert को बैठकर आकलन करना होगा तथा इसे जिला स्तर पर सूचित (Convey) करना होगा।

भारत सरकार कृषकों के आमदनी को दुगुना करना चाहती है। उन्होनें बतालाया कि राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत कितने किसान आच्छादित है, इसका सही आकड़ा उपलब्ध नहीं है।

7. कृषि निदेशक द्वारा बतलाया गया कि कृषि यांत्रिकरण योजना अन्तर्गत बैंकों से ऋण लेने में किसानों को असुविधा हो रही है। किसानों के खाते में RTGS के माध्यम से योजनाओं के अनुदान की राशि उपलब्ध कराने में काफी विलम्ब होता है। कुछ बैंकों द्वारा कृषकों को परेशान किया जा रहा है। उन्होने Custom Hiring Centre अन्तर्गत बैंकों से सहयोग हेतु सुझाव की मांग की।

(कार्रवाई–एस०एल०बी०सी०)

8. उप निदेशक(शष्य),पी०पी०एम० कोषांग द्वारा बतलाया गया कि कृषि यांत्रिकरण योजना अन्तर्गत Custom Hiring Centre में 80% अनुदान होने के उपरान्त राशि खर्च नहीं हो रही है। उन्होंने इस योजना अन्तर्गत किसानों को ऋण उपलब्ध कराने में आवश्यक सहयोग करने हेतु बैंक अधिकारियों से अनुरोध किया।

(कार्रवाई–एस०एल०बी०सी०)

9. निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना द्वारा बतलाया गया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन अन्तर्गत बहुत सारी योजनाएँ हैं जिसमें बैंकों के सहयोग की आवश्यकता है। योजनाओं की प्रति पूर्व में बैंकों को उपलबध करा दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक में योजनाओं के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में प्रशिक्षण भी दिया गया है परन्तु प्रगति नहीं हुई है। भारत सरकार की Custom Hiring Centre की योजना अन्तर्गत अन्य राज्यों में कार्य हुआ है परन्तु बिहार में नहीं हो रहा है। उन्होंने नवार्ड से एक training Schedule तैयार कर योजनाओं की जानकारी देने हेतु अनुरोध किया। राज्य की मिट्टी उपजाउ है, पानी पर्याप्त मात्रा में उपलबध है परन्तु Credit का आभाव है। उन्होंने सभी बैंकों में कृषि से सम्बन्धित एक विशेष सेल (Specialised Cell) बनाने पर बल दिया ताकि योजनाओं पर क्या कार्रवाई हो रही है इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। नए स्कीम आने पर उसे निर्मित सेल को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार की ओर से SLBC को एक पत्र लिखा जाय जिसमें सभी बैंकों के Controlling Head Office में एक Specialised Cell बनाया जाय तथा एक नोडल पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया जाय जो केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित (Central/State Govt Sponsored) योजनाओं की प्रगति से अवगत करा सके।

(कार्रवाई–एस०एल०बी०सी०,
मुख्य महाप्रबंधक, नवार्ड
सांख्यिकी कोषांग, कृषि निदेशालय)

10. संयुक्त निदेशक(शष्य) अभियंत्रण द्वारा बतलाया गया कि Custom Hiring Centre अन्तर्गत राज्य के सभी जिले में कुल 138 कृषि यंत्र बैंक स्थापित किए गए थे। 102 आवेदन भेजे गए थे जिसमें मात्र 20 आवेदन बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए तथा राशि खर्च नहीं हो सकी तथा भारत सरकार की यह योजना असफल हो गई। उपस्थित बैंक अधिकारियों द्वारा Custom Hiring Centre योजना की दिशा निर्देश (guide line) की प्रति उपलबध कराने हेतु अनुरोध किया गया। सहायक महाप्रबंधक, SLBC को दिशा निर्देश (guide line) की प्रति उपलब्ध करा दी गई तथा इसे सम्बन्धित बैंकों को उपलबध कराने का अनुरोध किया गया।

(कार्रवाई–एस०एल०बी०सी०)

11. केन्द्र/राज्य सरकार की विभिन्न योजना अन्तर्गत कोषागार से राशि निकासी के उपरानत DBT हेतु बैंकों को उपलब्ध कराया जाता है। राशि कुछ किसानों के खाते में नहीं जा पाता है तथा बैंक में

पड़ा रहता है। कुछ बैंक अधिकारियों द्वारा इसका कारण लाभार्थी का नाम/IFS कोड में गड़बड़ी बतलाया गया। कुछ बैंक अधिकारियों द्वारा खाता को आधार नम्बर से लिंक होने के बाद समस्या का स्वतः निवारण होने की जानकारी दी गई तथा आवेदक/लाभार्थी का नाम अंग्रेजी में लिखने का सुझाव दिया गया।

12. कुछ बैंक अधिकारियों द्वारा कृषि विभाग का एक Portal विकसित करने पर बल दिया गया ताकि सभी आवेदन Portal पर upload हो तो इसकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। निदेशक, उद्यान द्वारा वर्तमान में Farmers Database तैयार करने की जानकारी दी गई।
13. सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा एस० एल० बी० सी० की अगली बैठक दिनांक 10.08.17 को होटल चाणक्या, पटना में आयोजित करने की सूचना दी गई।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

8.8.2017

प्रधान सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 3358 दिनांक : 09-8-17

प्रतिलिपि : सहायक महाप्रबंधक, बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति संयोजक भारतीय स्टेट बैंक, प० गाँधी मैदान, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, नवार्ड, मौर्यालोक कम्पलेक्स ब्लॉक बी, चौथी एवं पांचवी तल्ला डाक बंगला रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.8.2017

प्रधान सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 3358 दिनांक : 09-8-17

प्रतिलिपि : निदेशक, पशु एवं मत्स्य विभाग, बिहार/निदेशक, डेयरी विकास, बिहार/निदेशक, उद्यान, बिहार/उप महाप्रबंधक, कम्फेड, बिहार/निदेशक, पी०पी०एम०, बिहार/संयुक्त निदेशक(शष्य), अभियंत्रण, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकरी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बिहार, पटना/उप निदेशक(शष्य), सूचना, बिहार, पटना/सहायक कृषि निदेशक(सा०), बिहार, पटना/उप निदेशक(शष्य), पी०पी०एम० कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.8.2017

प्रधान सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 3358 दिनांक : 09-8-17

प्रतिलिपि : उप सचिव, वित्त(सांस्थिक वित्त) विभाग, ललित भवन, बेली रोड, पटना/प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

8.8.2017

प्रधान सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।